Indian Council of World Affairs
Sapru House, Barakhamba Road
New Delhi

आईसीडब्ल्यूए अतिथि खंड

कोरियाई प्रायद्वीप पर ग्राउंड ज़ीरो से एक रिपोर्ट

राजदूत स्कंद आर तायल

1 जून, 2018

27 मई की सुबह जब कोरियन नेशनल डिप्लोमैटिक एकेडमी (केएनडीए) के साथ आईसीडब्ल्यूए प्रतिनिधिमंडल इंचियोन हवाई अड्डे पर उतरा, तो दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे-इन और उत्तर कोरिया के अध्यक्ष किम जोंग-उन के बीच एक दिन पहले हुई शिखर सम्मेलन की आश्चर्यजनक खबर के साथ इसका स्वागत किया गया। अप्रत्याशित शिखर सम्मेलनों, बैठकों, बयानों और खींजों की चली आ रही श्रृंखला में यह घटना एक नया पहलू था; जिसमें कोरियाई प्रायद्वीप को लेकर निरंतर चल रहे प्रकरण में चार मुख्य नायक लगे हुए हैं।

दक्षिण कोरिया से राष्ट्रपति के एक प्रत्याशित दौरे के मद्देनजर महानिदेशक राजदूत नलिन सूरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के लिए बातचीत की तारीखें निर्धारित की गई थीं। लेकिन केएनडीए, विदेश मंत्रालय, तीन थिंक टैंक तथा रूढ़िवादी और उदारपंथी रणनीतिक- दोनों ही तरह के विशेषज्ञों के साथ सभी औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में कोरियाई प्रायद्वीप का विकास प्रमुख विषय था।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और अध्यक्ष किम जोंग-उन के बीच शिखर सम्मेलन होगा भी या नहीं, होगा भी तो कब और कैसे होगा- यह सब केवल आनेवाले समय ही पता चल सकता है। लेकिन दक्षिण कोरिया के अधिकारियों और जानकारों के साथ स्पष्ट चर्चा ने उत्तर कोरिया के प्रति दक्षिण कोरिया की धारणाओं में बदलाव और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन की ओर दक्षिण कोरियाई रणनीतिक अभिविन्यास में फिर से प्रमुख समायोजन का खुलासा किया।

1945 में देश की बड़ी शक्ति द्वारा थोपे गए विभाजन और उसके बाद दक्षिण कोरियाई राजनीति व्यापक तौर पर दो विचारधाराओं के बीच बंट कर रह गयी। परंपरावादी अमेरिका के करीब हैं, चीन के प्रति उनका गहरा अविश्वास हैं और सख्त पारस्परिकता के आधार पर उत्तर कोरिया के साथ सुलह की नीति का पालन करते हैं। वहीं उदारवादी, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति मून जे-इन करते हैं; अमेरिका से सावधान रहे हैं और चीन के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं और उत्तर कोरिया के साथ सामंजस्य बनाने के लिए आगे बढ़ कर पहल करने को तैयार हैं। निर्वासन के मामले में उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच चल रहे आंतरिक बातचीत के बीच, डीपीआरके के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए परंपरावादियों ने इस मुद्दे को उठाया कि किम जोंग-उन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। उदारवादियों जवाब यह है कि भरोसा अब बातचीत के माध्यम से बनाया जा रहा है और दोनों में से किसी को अतीत में कैद होकर नहीं रहना चाहिए।

इसके परमाणु हथियारों और आईसीबीएम क्षमता का परित्याग करने के मामले को लेकर उत्तर कोरिया की नियत को लेकर परंपरावादियों में संशय है। उदारवादियों का मानना है कि एक समान आर्थिक विकास और शांति संधि के रूप में मान्यता के साथ प्रस्तावित लाभों की तुलना में परमाणु विकल्प को आगे बढ़ाने में उत्तर कोरिया की लागत बहुत छोटी-सी है।

दक्षिण कोरिया में शांति के लिए राजी होने के किम जोंग-उन की मंशा अनिश्चित है। हालांकि, आम सहमति यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अप्रैल 2017 में लगाए गए प्रतिबंधों की गंभीरता

और इन प्रतिबंधों को पूरी तरह से लागू करने के लिए चीन पर राष्ट्रपति ट्रम्प के अथक दबाव से उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा; पर अस्थायी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी के प्रो. ली सोंग-सूक के अनुसार, मई 2016 में वर्कर्स पार्टी की 7वीं कांग्रेस, जिसने किम जोंग-उन के उत्तराधिकार को औपचारिक मान्यता दी गयी थी, के बाद से उत्तर कोरियाई राजनीति में धीरे-धीरे बदलाव आया है। इसके बाद जून 2016 में सुप्रीम पीपुल्स असेंबली ने किम जोंग-उन के साथ 'स्टेट अफेयर्स कमीशन' (एसएसी) बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया। यह वह उपाधि है जिससे उत्तर कोरियाई नेता को अब उत्तर कोरियाई मीडिया और दुनिया द्वारा पहचाना जाता है। आयोग ने 'नेशनल डिफेंस कमीशन' का स्थान ले लिया है, जिसने उत्तर कोरिया पर पहले किम जोंग-इल की अध्यक्षता में शासन किया था। एसएसी ने कथित तौर पर 'सोंगुन' (पहले सेना) सिद्धांत का परित्याग किया, जो यह दर्शाता है कि 'सोंगुन राजनीति' अब उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ की विचारधारा नहीं है। इन कदमों से उत्तर कोरिया की पार्टी, सेना और सरकार के बीच संबंधों में एक बुनियादी बदलाव आया है, जिसे 20 अप्रैल 2018 को 7वीं सेंट्रल कमिटी की 3री बैठक में सम्मिलित कर लिया गया था।

20 अप्रैल को प्लेनम किम जोंग-उन ने उत्तर कोरिया को 'समाजवादी आर्थिक निर्माण' का नया रणनीतिक उद्देश्य घोषित किया और घोषणा की कि उत्तर कोरिया आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय माहौल बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें पड़ोसी देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ 'निकट संपर्क और सक्रिय संवाद' शामिल है।

आर्थिक पुनर्निर्माण और शासन की स्थिरता की दक्षिण कोरिया की ईमानदारी पेशकश के मद्देनजर राष्ट्रपति मून स्पष्ट रूप से उत्तर कोरिया के अध्यक्ष किम को समझाने में सक्षम रहे हैं और दोनों नेताओं के पास 26 मई को अपने दूसरे शिखर सम्मेलन द्वारा आपसी समझ और विश्वास को जाहिर करने का एक उल्लेखनीय मौका है।

राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा आयोजित 'कूटनीति की नई शैली' के साथ तालमेल बिठाना राष्ट्रपति मून के लिए चुनौती है। दक्षिण कोरिया में जनता के मूड में एक महत्वपूर्ण बदलाव उन युवाओं की वजह से है, जो पहले उत्तर में बसे अपने परिजनों के साथ पुनर्मिलन या सामंजस्य जैसी किसी भी बात के प्रति उदासीन थे। हाल के चुनावों ने इस बात का खुलासा किया कि युवाओं के बीच एक सकारात्मक दिलचस्पी और समर्थन से उत्तर और दक्षिण के बीच हाल ही में वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगी है। राष्ट्रपति मून की अनुमोदन रेटिंग लगातार 70% के आसपास रही है और इस तरह से उनका हाथ मजबूत हुआ है।

दक्षिण कोरियाई मीडिया और विशेषज्ञों की राय है कि कोरियाई प्रायद्वीप पर चल रही शांति और सुलह प्रक्रिया में चीन को हाशिए पर कर दिए जाने से वह बहुत नाखुश है। 26 मार्च और 7 मई को चेयरमैन किम के साथ अपने दो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति शी जिन-पिंग ने कोरियाई प्रायद्वीप के मामले में किसी भी भावी समझौतों में चीन के अपने हितों और केंद्रीयता का दो ट्क शब्दों में जिक्र किया और कोरियाई युद्ध में दोनों प्रमुख भागीदारों में खुद को उत्तर कोरियाई सुरक्षा की गारंटी देनेवाला बताया।

दक्षिण कोरियाई नीति निर्माताओं को चिंता इस बात की है कि चीनी कंपनियां धीरे-धीरे कोरियाई उत्पादों को अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजार में बदल रही हैं।

दक्षिण कोरिया के विद्वान इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उसे चीन के साथ नेटवर्किंग के प्रसार के लिए आगे बढ़ाना है या अमेरिका और जापान के साथ संबंधों को व्यापक बनाना है; क्योंकि 2030 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए चीनी अर्थव्यवस्था का आगे निकल जाना उसकी अनिवार्यता को समाप्त करना है। एशिया-प्रशांत के प्रति अमेरिका के असंतुलन की सीमा और स्थायित्व की गुंजाइश, जिसे राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शुरू किया था और ट्रम्प प्रशासन द्वारा इसे आगे बढ़ाए जाने का भी लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। हालांकि दक्षिण कोरियाई मानते हैं कि किसी तरह के भावी एशियाई रणनीतिक वास्तुकला में चीन को शामिल किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि 19वें पार्टी कांग्रेस के बाद चीन ने 'शक्तिशाली राष्ट्र रणनीति' तैयार की है और एशिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को तेजी से आकार देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। हालांकि चीन बनाम अमेरिका में सैन्य तौर पर चीन अभी भी कमजोर स्थिति में है और उसके लिए अमेरिका को सीधे चुनौती देने का यह सही समय नहीं है। लेकिन चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रमिक पतन और चीन की अपरिहार्यता पर भरोसा है कि वह पहले आर्थिक, बाद में सैन्य क्षमता में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। दक्षिण कोरियाई रणनीतिक विश्लेषक तेजी से बदलते रणनीतिक समीकरणों से निपटने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं और 'मझोले शक्तियों के गठबंधन' की व्यवहार्यता पर विचार कर रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में मौजूदा वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति मून जे-इन और अध्यक्ष किम जोंग-उन की तुलना में एक तरफ राष्ट्रपति मून और राष्ट्रपति ट्रम्प तथा दूसरी तरफ अध्यक्ष किम और राष्ट्रपति शी के बीच रणनीतिक समझ, संपर्क और उद्देश्यों के प्रति झुकाव कहीं बेहतर है। 27 अप्रैल को पनमुनजोम घोषणा का दोनों कोरिया द्वारा अनुसरण किए जाने की संभावना है, लेकिन उनके कूटनीतिक कौशल की सीमा का परीक्षण अप्रत्याशित ट्रम्प और संदिग्ध चीन द्वारा किया जाएगा।

***